(123)

प्रेषक,

नितेश कुमार झा, अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में.

निदेशक, पर्यटन निदेशालय, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग-1

देहरादून दिनांक 2) अक्टूबर, 2011

विषय:--मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा अन्तर्गत पौड़ी में 60 शैय्याओं के अतिरिक्त पर्यटन आवास गृह की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—232 / VI / 2005—44 (पर्य0) / 2005, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा पौड़ी में अतिरिक्त पर्यटक आवास गृह अनुमानित लागत ₹ 56.37 लाख के आगणन पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही ₹ 10.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। तदोपरान्त शासनादेश संख्या—1374 / VI(1) / 2011—2(27) / 2010, दिनांक 20 जून, 2011 द्वारा आगणन की अवशेष धनराशि ₹ 46.37 लाख अवमुक्त की गयी। अब मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत पूर्व स्वीकृत 20 शैय्याओं के अतिरिक्त पर्यटक आवास गृह को उच्चीकृत करते हुए आप द्वारा शासन को उपलब्ध कराये गये 60 शैय्याओं के पर्यटक आवास गृह के आगणन अनुमानित लागत ₹ 341.57 लाख पर टी०ए०सी० वित्त के परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गयी धनराशि ₹ 329.91 लाख (₹ तीन करोड़ उन्नतीस लाख इक्यानबे हजार मात्र) पर चालू वित्तीय वर्ष 2011—12 में राज्य सेक्टर की चालू योजनान्तर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दिये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2— योजना से सम्बन्धित उपरोक्त उल्लिखित शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 2005 एवं दिनांक 20 जून 2011 द्वारा पूर्व स्वीकृत 20 शैय्याओं के पर्यटक आवास गृह के निर्माण हेतु अवमुक्त ₹ 56.37 लाख की धनराशि 60 शैय्याओं के पर्यटक आवास गृह अनुमानित लागत ₹ 329.91 लाख के आगणन में समायोजित समझी जाय और अवशेष ₹ 273.54 लाख (₹ दो करोड़ तिहत्तर लाख चौवन हजार मात्र) पूर्व में अवमुक्त धनराशि के उपयोग के बाद अवमुक्त किया

जायेगा।

3— कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरे शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियंता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

4— कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से

प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

5— कार्य पर उत्तना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6 एक मुख्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी

से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

7— कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोठनिठविठ द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।



8— कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का मली—भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य करायां जाय।

9— रवीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2012 तक अवश्य कर लिया

जाय।

- 10— निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।
- 11- एक योजना हेतु स्वीकृत धनराशि का व्यय दूसरी योजना पर कदापि न किया जाय।
- 12— मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या—2047 / XIV—219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन किया जाय।
- 13— व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।
- 14— पूर्व में अवमुक्त धनराशि सम्बन्धित शासनादेशों में उल्लिखित लेखाशीर्षक में व्यय की जायेगी।
- 15— उपरोक्त योजना की स्वीकृति एवं धनराशि अवमुक्त से सम्बन्धित पूर्व शासनादेशों में उल्लिखित सभी शर्ते यथावत रहेंगी।
- 16— उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ०शा०सं०—620 / XXVII(2) / 2011, दिनांक 21 अक्टूबर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय.

(नितेश कुमार झा) अपर सचिव।

संख्या:- 2505 /VI(1)/2011-44(पर्य0)2004, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
- 3- आयुक्त गढ़वाल मण्डल।
- 4- जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल।
- 5— सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 7- मा० मुख्यमंत्री कार्यालय, घोषणा अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
- 8- . निजी सचिव-मा० पर्यटन मंत्री, मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 9- जिला पर्यटन विकास अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
- 10- वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
- 11 एन0आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
- 12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से, (श्याम सिंह) अनुसचिव।